I.T.D.Ps. in Rajasthan

6848. SHRI JAI NARAIN ROAT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Integrated Tribal Development Projects Operating in Rajasthan at present, and

(b) the progress of each project in that State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Rajasthan has five Integrated Tribal Development Projects.

(b) I.T.D.P. wise allocation and expenditure have not been maintained by the State Government. However, allocation and expenditure incurred in the tribal sub-plan areas consisting of these five I.T.D.Ps. are as under:—

Year	Allocation (Rs. in lakhs)	Expenditure
1974—78 .	7223·65	7172·81
1978-79 .	3476·03	3138·71
1979-80 .	4083·41	3824·38
1980-81 .	4652·95	2282·33
TOTAL .	19436·04	16418·23

Supply of uniform of Class IV employees

6849. SHRI MOTI LAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cloth for uniforms of Class IV employees in the Central Government is of rough quality;

(b) whether it is also a fact that the cloth for uniforms of class IV staff in public undertakings is of superior quality than supplied to class IV employees in the Central Government; and

(c) if so, whether Government proposed to improve the quality of cloth supplied to Class IV staff in the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) At present special dasuti khadi cloth in fast biscuit colour is used for summer uniforms of the Class IV employees in the Central Government. Woolen Khadi is used for winter uniforms for them.

(b) According to the Bureau of Public Enterprises, khadi is used for the fabrication of uniforms of the employees working in the public enterprices *except* where khadi uniforms militate against functional efficiency, e.g., safety regulations, etc. The National Textile Corporation has, however, been exempted, to the extent the cloth produced by its units can be used for the uniforms of its employees.

(c) The quality of cloth presently prescribed has been decided in 1980 in agreement with the Staff Side of the National Council of the J.C.M. representing the Central Government employeese including Class IV and, hence, the question of changing the quality specification of the cloth does not arise at present.

विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति के प्रतिवेदन दिए जाने मे विलम्ब

6850. **श्री अनवर अहमद :**

श्री भीखा भाई :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय में विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति ने अपना प्रतिवेदन देने में 6 वर्ष से अधिक समय लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के पेश किये जाने तथा उसे क्रियान्वित किये जाने में इतने विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) सरकार कर्मचारियों को इसके लाभ कब प्रदान करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग). विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति ने नवम्बर 1975 में काम शुरू किया और मई 1979 अर्थात साढ़े तीन वर्ष में इसने अपना काम पूरा कर लिया था । तीन लाख से अधिक कामगरों के संबंध में पुनर्वर्गीकरण कार्य की मात्रा और उसकी जटिलता को देखते हुए समिति द्वारा उसे निपटाने में लगा समय बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता । समिति ने जिन वेतनमानों के लिए सिफारिश की थी उनके विरुद्ध रक्षा कामगरों द्वारा अभ्यावेदन देने की वजह से तथा उनके द्वारा रेलवे के वेतनमानों के मुताबिक ग्रेड संरचना की मांग किए जाने की वजह से समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का काम रुक गया था । इसके लिए दूसरी समिति नियुक्त करना जरुरी हो गया था । इन दोनों समितियों की सिफारिशों की जांच की जा चुकी है और आशा है कि औद्योगिक कामगरों की ग्रेड-संरचना के बारे में निकट भविष्य में निर्णय ले लिया जाएगा । गैर-औद्योगिक कामगरों से संबंधित सिफारिशों पर भी कार्रवाई की जा रही है ।

वायु सेनाध्यक्षों की सेवावधि बढ़ाया जाना

6851. **श्री चतुभूंज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेनाध्यक्ष की सेवा अवधि कब समाप्त होगी ;

(ख) क्या उनकी सेवावधि कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को अनुवर्ती अधिकारी पर इस सेवावधि के बढ़ाये जाने के प्रतिकूल प्रभाव की पूरी जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख). वायु सेनाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और इस में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन सरकार ने एयर चीफ मार्शल के रैंक में वायु सेनाध्यक्ष की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक वर्तमान वायु सेनाध्यक्ष की सेवा अवधि को 31 अगस्त, 1981 तक अर्थात जब वह इस पद में 3 वर्ष की अवधि पूरी करेंगे तब तक बढ़ाया जाएगा ।

(ग) उपर्युक्त फैसला करते समय सरकार ने इस बात का इतमीनान कर लिया है कि परवर्ती अफसरों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(घ) उपर्युक्त फैसला करने में सरकार इस उद्देश्य को लेकर चली है कि वायु सेनाध्यक्ष का कार्यकाल थल सेनाध्यक्ष और नौ-सेनाध्यक्ष के कार्यालय के बराबर लाया जाए ।

Finalisation of Annual Plan for 1981-82 of the West Bengal

6852. SHRI SANAT KUMAR MANDAL: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government of West Bengal have submitted their draft annual plan for 1981-82;